

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के माह 08/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव व श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08/01/2018 से 11/01/2018 एवं श्री निरज चुंगू, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: प्रथम लेखापरीक्षा।

- (ii) (i) इकाई के क्रयकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जनपद नैनीताल व उधम सिंह नगर के अन्तर्गत लो.नि. व. के कार्यों का सुपर वजन।
- (iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	8793088	8793088	-	-	-	-
2017-18	-	-	17378039	13265794	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय ववरण निम्नवत है: शून्य

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
			शून्य		

- (iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लो.नि. व.



प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लो.नि. व., उत्तराखण्ड



मुख्य अभियन्ता, लो.नि. व., उत्तराखण्ड



अधीक्षण अ भयन्ता ,लो.नि. व.



अ धशासी अ भयन्ता,लोक निर्माण वभाग

- (v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी के माह माह दिसम्बर 2016 से नवम्बर 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 02/2017 को वस्तुत जांच हेतु चयनित कया गया।
- (vi) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानको के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर- (1) कार्यों पर समय वृद्ध प्रदान करने हेतु एस. बी. डी. में अनियमित अधिकारों का निर्धारण किया जाना।

शासन के पत्र संख्या 928/III(2)14-75(सा.)/200 टी.सी. दिनांक 10/02/2014 द्वारा ई प्रॉक्चूरमेंट पद्धति के अंतर्गत निवदा प्रक्रिया में एक रूपता लाने हेतु **Standard Bidding document** (एस. बी. डी.) लागू करने के लिये प्रमुख अभ्यंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, द्वारा पत्र संख्या 520/24 सा. प्र.14 दिनांक 01/05/2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त तिथि दिनांक 24/02/2014 के पश्चात् 1.50 करोड़ से अधिक कार्यों को जो भी निवदा आमंत्रित किया जाएगा उनमें अनुबन्ध में एस.बी.डी ही लगाई जाये।

कार्यालय मुख्य अभ्यंता, लो.नि. व., हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में अधीक्षण अभ्यंता/अधशासी अभ्यंता द्वारा 1.50 करोड़ से अधिक कार्यों हेतु एस.बी.डी. के माध्यम से निवदा तो आमंत्रित की लेकिन अनुबन्ध में एस. बी. डी. क्लॉज 06 व 07 को भाग न बनाकर जी.पी. डबल्यू 09 में समय वृद्ध हेतु प्रवधान किये गये थे। जो उचित नहीं है व उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देशों के वरुद्ध था। आगे कार्यालय के अभिलेखों एवं पत्रावली में पाया गया कि कई कार्य पर दोनों जी.पी. डबल्यू-09 व एस.बी.डी लगाये गये थे लेकिन इन कार्यों पर समय वृद्ध **delegation of powers 2010** व जी.पी.डबल्यू-9 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं दिया था क्योंकि एस.बी.डी के अनुसार सक्षम अधिकारी मुख्य अभ्यंता (दो करोड़ के ऊपर के कार्यों हेतु **accepting authority of tender**) के वरुद्ध अधशासी अभ्यन्ता से समय वृद्ध प्राप्त किए जाने के अधिकार प्राप्त थे (**as per the definition of Engineer given in PCC**) उक्त का संज्ञान लेते हुये वभागाध्यक्ष द्वारा अनुबन्ध गठित करने वाले अधिकारी अधीक्षण को समय वृद्ध प्रधान करने की शक्ति दी जो कि **delegation of powers 2010** (2 करोड़ के ऊपर कार्यों हेतु) व जी.पी.डबल्यू-9 के क्लॉज 7 में दिये गये प्रावधानों¹ के वरुद्ध भी है क्योंकि 1.50 करोड़ से कम के कार्यों में मुख्य अभ्यंता स्तर से समय वृद्ध प्राप्त किए जाने के प्रावधान है जब कि 2 करोड़ से ऊपर कार्यों में एस.बी.डी में दिये गये प्रावधान वपरीत है जिसके अनुसार मुख्य अभ्यन्ता को समय वृद्ध प्रदान करने का अधिकार की व्याख्या स्पष्ट नहीं की गयी है।

इस ओर इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि एस.बी.डी. में **Engineer की Definition** के अनुसार 1.50 करोड़ व उससे अधिक कार्यों के लिए समय वृद्ध प्रदान करने के लिए अधशासी अभ्यंता सक्षम है लेकिन प्रमुख अभ्यंता, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के पत्रांक-614/24(2) याता.क/2017 दिनांक-10/10/2017 से दिये गए निर्देशानुसार अधीक्षण अभ्यंता द्वारा समयवृद्ध स्वीकृति की कार्यवाही की गयी। उत्तर

¹ The cases of the extension of the time beyond the time schedule as per milestone shall be submitted to the authority next higher to the officer accepting the contract on behalf of the Government provide that the extension of time should be limited to 50% of the total period of that particular miles stone. In case this period exceeds more than-50%, it shall be submitted to authority next to next higher to the office accepting the contract as the case may be.

तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एस.बी.डी. में सक्षम अधिकारी मुख्य अभियंता (दो करोड़ के ऊपर से कार्यों हेतु **accepting authority of tender**) के वरुद्ध अधिशासी अभियन्ता से समय वृद्धि प्राप्त किए जाने के अधिकार प्राप्त थे (**as per the definition of Engineer given in PCC**) उक्त का संज्ञान लेते हुये वभागाध्यक्ष द्वारा अनुबन्ध गठित करने वाले अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता को समय वृद्धि प्रदान करने की शक्ति दी जो कि **delegation of powers 2010** (2 करोड़ के ऊपर कार्यों हेतु) व जी.पी.डब्ल्यू-9 के क्लॉज 7 में दिये गये प्रावधानों² के वरुद्ध भी है क्योंकि 1.50 करोड़ से कम के कार्यों में मुख्य अभियंता स्तर से समय वृद्धि प्राप्त किए जाने के प्रावधान है जबकि 2 करोड़ से ऊपर कार्यों में एस.बी.डी में दिये गये प्रावधान वपरीत है जिसके अनुसार मुख्य अभियन्ता को समय वृद्धि प्रदान करने का अधिकार की व्याख्या स्पष्ट नहीं की गयी है।

अतः कार्यों पर समय वृद्धि प्रदान करने हेतु एस.बी.डी. में अनियमित अधिकारों के निर्धारण किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

² The cases of the extension of the time beyond the time schedule as per milestone shall be submitted to the authority next higher to the officer accepting the contract on behalf of the Government provide that the extension of time should be limited to 50% of the total period of that particular miles stone. In case this period exceeds more than-50%, it shall be submitted to authority next to next higher to the office accepting the contract as the case may be.

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
	प्रथम लेखापरीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		NA		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

1) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधशासी अभियन्ताओं द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

श्री बी.सी.बिनवाल	मुख्य अभियन्ता	28/12/2013 से अब तक
-------------------	----------------	---------------------

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

ब.लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2